करेंट अफेयर्स राजस्थान

अप्रैल (संग्रह)

2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

राजस्थान **3**

- मेडिफेस्ट-2022 3
- नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान समूचे देश में अग्रणी 3
- आरटीआई पोर्टल 2.0 लॉन्च 4
- मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट वैन 4
- ऑपरेशन समानता 4
- राजस्थान मंत्रिमंडल के महत्त्वपूर्ण निर्णय 5
- रूफटॉप सोलर में राजस्थान दूसरे पायदान पर 5
- राजस्थान के तापीय विद्युतगृहों को मिलेगा छत्तीसगढ़ से कोयला 6
- संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 6
- मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद के कार्यकाल में वृद्धि 7
- तीन राष्ट्रीय राजमार्गों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा सड़क दुर्घटनामुक्त 7
- सांस्कृतिक कार्यक्रम 'फोक सफर' का आयोजन 8
- एपीआई का 77वाँ राष्ट्रीय सम्मेलन 'एपिकॉन, 2022' 8
- राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम व टीएचडीसी के बीच अक्षय ऊर्जा पार्क के लिये करार 8
- राजस्थान में स्थापित हुआ एल-रूट सर्वर 9
- अब तक 143 हेरिटेज संपत्तियों को प्रमाण-पत्र जारी 9
- स्मार्ट सिटी रैंकिंग में उदयपुर दूसरे स्थान पर 10
- राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, 2022 10
- इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी और 23 राज्य विश्वविद्यालयों के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित 11
- मार्च 2022 में राज्य का सभी वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक 380.58 रहा 11
- लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये चूरू ज़िला कलक्टर सम्मानित 12
- जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट के लिये 672.5 करोड़ रुपए की मंज़ूरी 13
- तीन दिवसीय 69वीं राज्यस्तरीय सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ 13
- राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2022 के लोगो का विमोचन 13
- नवजीवन योजना 14
- आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण 14
- ब्लॉक हेल्थ मेले का शुभारंभ 15
- आईबीसी एक्सीलेंस अवार्ड, 2021 15
- स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली 'गगन' का इस्तेमाल 16

नोट :

राजस्थान

मेडिफेस्ट-2022

चर्चा में क्यों ?

31 मार्च, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में मेडिफेस्ट-2022 के लोगो का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- दोदिवसीय मेडिफेस्ट-2022 का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा 5 अप्रैल को किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 5 अप्रैल को एसएमएस अस्पताल में बनने वाले 24 मंजिला नए आईपीडी टावर एवं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्डियोलॉजी का भूमिपूजन तथा शिलान्यास भी किया जाएगा।
- साथ ही, एसएमएस मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में 5 अप्रैल को ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रदर्शनी का उद्घाटन भी होगा।
- मेडिफेस्ट-2022 के दौरान 18 इंटरेक्टिव सेशन में विशेषज्ञ विभिन्न बीमारियों एवं उनके उपचार में काम आने वाली आधुनिक तकनीक के बारे में जानकारी देंगे।
- आईपीडी टावर एवं कॉर्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बनने से एसएमएस हॉस्पिटल में 1200 बेड की क्षमता बढ़ जाएगी। साथ ही 20 ऑपरेशन थियेटर, 4 कैथ लैब एवं 100 ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर भी बढ़ेंगे।

नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान समूचे देश में अग्रणी

चर्चा में क्यों ?

2 अप्रैल, 2022 को राजस्थान ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व चेयरमैन आरआरईसी (राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम) डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है।

प्रमुख बिंदु

- डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में 49,346 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित में राजस्थान 10,506 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित कर समूचे देश में शीर्ष पर आ गया है।
- केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 7,534 मेगावाट क्षमता के साथ कर्नाटक दूसरे और 6,309 मेगावाट क्षमता के साथ गुजरात तीसरे स्थान पर है।
- डॉ. अग्रवाल ने बताया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में 3,000 मेगावाट क्षमता से अधिक क्षमता विकसित की जा चुकी है, जबकि पिछले तीन सालों में प्रदेश में 6,552 मेगावाट क्षमता विकसित हुई है।
- रूफटॉप में भी राजस्थान तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 10,506 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता में 9,542 मेगावाट क्षमता ग्राउंड माउंटेड, 668 मेगावाट रूफटॉप और 296 मेगावाट सौर ऊर्जा ऑफग्रिड क्षेत्र में विकसित की गई है।
- गौरतलब है कि हाल ही में किये गए एमओयू व एलओयू समझौतों से राजस्थान अब देश के सबसे बड़े सोलर हब के रूप में विकसित होने जा रहा है। प्रदेश में इन्वेस्ट राजस्थान के तहत किये गए एमओयू एलओआई में से 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू एलओआई केवल ऊर्जा क्षेत्र में ही हस्ताक्षरित हुए हैं।

आरटीआई पोर्टल 2.0 लॉन्च

चर्चा में क्यों ?

4 अप्रैल, 2022 को राज्य में सूचना के अधिकार के तहत मामलों के त्वरित निस्तारण के लिये राज्य सूचना आयोग द्वारा आरटीआई पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया।

प्रमुख बिंदु

- राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त डी.बी. गुप्ता ने सूचना आयोग कार्यालय में आरटीआई पोर्टल को लॉन्च किया। वर्तमान में 275 विभाग पोर्टल से जुड़े हैं।
- इस पोर्टल के माध्यम से राज्य में दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को भी आरटीआई में अपील दायर करने में सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन दायर द्वितीय अपील की स्वीकार्यता, अस्वीकार्यता, प्रथम सुनवाई नोटिस तथा केस संख्या भी प्रार्थी को ऑनलाइन प्राप्त हो सकेंगी।
- नागरिक ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग कर या ई-मित्र की सहायता से आवेदन दाखिल करने के साथ-साथ आवेदन शुल्क भी ऑनलाइन जमा करा सकेंगे। इसके अलावा द्वितीय अपील के नोटिस और पत्र आदि भी एसएमएस व ईमेल के माध्यम से स्वत: पहुँचेंगे। इससे प्रकरणों के निस्तारण में तेज़ी आएगी।

मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट वैन

चर्चा में क्यों ?

4 अप्रैल, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिवालय परिसर से राजस्थान पुलिस की मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट (एमआईयू) वैनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रमुख बिंदु

- ये एमआईयू वैन ज़िला मुख्यालय से दूर स्थित थानों में उपयोग में लाई जाएंगी। इनकी सहायता से दूरस्थ स्थानों पर होने वाली घटनाओं में त्वरित कार्यवाही की जा सकेगी और अनुसंधान में लगने वाला समय भी बचेगा।
- इस अवसर पर राज्य के पुलिस महानिदेशक एम.एल. लाठर ने बताया कि एमआईयू उपलब्ध होने से जाँच अधिकारी त्वरित गति से मौके पर पहुँचेंगे और गैजेट्स की मदद से मौके पर ही अनुसंधान किया जा सकेगा।
- इससे गवाहों को बुलाना नहीं पड़ेगा और जाँच का औसत समय कम होने के साथ ही इन्वेस्टिगेशन क्वालिटी में भी सुधार होगा।
- गौरतलब है कि पुलिस आधुनिकीकरण योजना 2021-22 के तहत करीब 71 एमआईयू वैन पुलिस को सौंपी जाएंगी। इनमें से अभी तक 48 एमआईयू पुलिस को प्राप्त हो चुकी हैं।

ऑपरेशन समानता

चर्चा में क्यों ?

5 अप्रैल, 2022 को राजस्थान के राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने बूंदी ज़िले में ज़िलास्तरीय अधिकारियों की बैठक में 'ऑपरेशन समानता' की तर्ज़ पर अनुसूचित जाति वर्ग के अन्य मामलों में अभियान स्तर पर कार्य किये जाने का निर्देश दिया।

प्रमुख बिंदु

- 24 जनवरी से शुरू हुआ ऑपरेशन समानता बूंदी पुलिस का नवाचार है, जिसे अब पूरे प्रदेश में क्रियान्वित किया जा रहा है।
- इसके तहत थानास्तर पर बीट कॉन्स्टेबलों को अपने क्षेत्र में ऐसे गाँवों को चिह्नित करना होता है, जहाँ अब तक दलित दूल्हे घोड़ी पर नहीं बैठे हों या घोड़ी पर बैठने पर अप्रिय घटना हुई हो या उन्हें घोड़ी से उतार दिया गया हो।

- चिह्नित करने के बाद ऐसे गाँवों में समानता समितियाँ बनाई जाती हैं ताकि घोड़ी पर दलित समाज के दूल्हे, दुल्हनों की बिंदौरियाँ बिना किसी विवाद और अप्रिय घटना के निकाली जा सकें।
- गौरतलब है कि संविधान के भाग 3 के तहत प्रदत्त समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14-18) के बावजूद SC/ST समुदायों के साथ अश्पृश्यता सहित विभिन्न प्रकार के भेदभाव किये जाते हैं। ऐसे में राजस्थान पुलिस का यह कदम अत्यंत सराहनीय है।

राजस्थान मंत्रिमंडल के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

6 अप्रैल, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसायटी के गठन तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप-प्रधानाचार्य के कैडर का गठन करने सहित अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप-ज़िला अस्पताल, ज़िला अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज सहित सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में नि:शुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नामकरण 'मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान योजना' किये जाने का निर्णय लिया गया।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस वित्तीय वर्ष के बजट में प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में नि:शुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार उपलब्ध कराने की घोषणा की थी।
- मंत्रिमंडल ने पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसायटी के गठन का निर्णय किया है। इस सोसायटी द्वारा प्रस्तावित सर्वोत्तम श्रेणी के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का संचालन किया जाएगा।
- इससे राज्य में सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों एवं अन्य हितधारकों की क्षमता को अधिक समग्र एवं व्यापक बनाया जा सकेगा। इस सोसायटी का राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 के तहत पंजीयन कराया जाएगा।
- मंत्रिमंडल ने राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम (द्वितीय संशोधन), 2022 का अनुमोदन किया है। इससे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक कार्यों के सुचारु संचालन तथा पर्यवेक्षण को बेहतर बनाने के लिये उप-प्रधानाचार्य (लेवल-14) के पद का कैडर स्थापित किया जा सकेगा।
- मंत्रिमंडल ने राजस्थान ज़िला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम-1986 (नियम 7-ग) में संशोधन को मंज़ूरी दी है। मंत्रिमंडल के निर्णय से इस नियम में विहित 'उत्कृष्ट खिलाड़ियों' की अभिव्यक्ति को अधिक स्पष्टता और व्यापकता प्रदान की जा सकेगी, जिससे पात्र खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।
- मंत्रिमंडल ने श्रीगंगानगर में मिनी सचिवालय के निर्माणकार्य के लिये राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

रूफटॉप सोलर में राजस्थान दूसरे पायदान पर

चर्चा में क्यों ?

6 अप्रैल, 2022 को अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा एवं चेयरमैन राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम डॉ. सुबोध अग्रवाल ने अक्षय ऊर्जा निगम में अधिकारियों की समीक्षा बैठक में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा फरवरी, 22 की जारी रिपोर्ट के अनुसार रूफटॉप सोलर योजना के क्रियान्वयन में गुजरात के बाद राजस्थान दूसरे नंबर पर आ गया है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित कर राजस्थान सौर ऊर्जा में पहले से ही प्रथम पायदान पर है। बंजर भूमि पर सोलर सिस्टम लगाने की कुसुम योजना के क्रियान्वयन में भी राजस्थान अग्रणी प्रदेश बना हुआ है।

- डॉ. अग्रवाल ने बताया कि रूफटॉप सोलर में प्रदेश में 748 मेगावाट क्षमता विकसित की जा चुकी है। राज्य में अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा योजनाबद्ध तरीके से रूफटॉप सोलर योजना का क्रियान्वयन किया गया है।
- रूफटॉप सोलर योजना को और अधिक सरल बनाने के लिये अब स्टेट पोर्टल के स्थान पर नेशनल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकेगा। इसी तरह से रूफटॉप सिस्टम लगाने के लिये अब एमएनआरई के एंपेनल्ड वेंडर के साथ ही स्वयं अपने स्तर पर भी सिस्टम लगाने की सुविधा होगी।
- रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने पर आने वाले व्यय को आरंभ में लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा और फिर अनुदान राशि सीधे लाभार्थी को जारी की जाएगी।
- इसके साथ ही नई सरलीकृत व्यवस्था के तहत लाभार्थी सरकार के एंपेनल्ड वेंडर या स्वयं अपनी पसंद का सिस्टम लगाने के लिये स्वतंत्र होंगे। लाभार्थी पर किसी तरह की मैक विशेष का सिस्टम या वेंडर विशेष से ही सिस्टम लगाने की बाध्यता नहीं होगी।

राजस्थान के तापीय विद्युतगृहों को मिलेगा छत्तीसगढ़ से कोयला

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को छत्तीसगढ़ के सरगुजा स्थित परसा कोल ब्लॉक में खनन कार्य आरंभ करने के लिये छत्तीसगढ़ सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से क्लियरेंस मिल गई है। इस नए ब्लॉक में कोयले का खनन कार्य आरंभ होते ही राज्य के तापीय विद्युतगृहों के लिये अतिरिक्त कोयला मिलने लगेगा।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले दिनों 25 मार्च को ऊर्जा मंत्री भँवर सिंह भाटी व अधिकारियों के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से परसा कोल ब्लॉक और परसा ईस्ट कांटा बासन कोल ब्लॉक द्वितीय चरण में कोयले का खनन आरंभ करने की शीघ्र अनुमति देने का आग्रह किया था।
- छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले दिन ही पारसा ईस्ट कांटा बासन कोल ब्लॉक के द्वितीय चरण की कोल माइनिंग की अनुमति दे दी, वहीं 6 अप्रैल को राज्य के नए कोल ब्लॉक परसा कोल ब्लॉक में भी कोयला खनन की अनुमति दी है।
- विद्युत उत्पादन निगम को कोयला खनन की आवश्यक तैयारियाँ शीघ्र पूरी करने के निर्देश दे दिये गए हैं और आवश्यक तैयारियाँ आरंभ कर दी गई हैं।
- एसीएस माइंस, पेट्रोलियम व एनर्जी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को 841.538 हेक्टेयर क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के सरगुजा परसा कोल ब्लॉक 2015 में आवंटित किया गया था। केंद्र सरकार व छत्तीसगढ़ सरकार से क्लीयरेंस मिलने के बाद इस नए ब्लॉक में खनन कार्य किया जाएगा।
- इस नए परसा कोल ब्लॉक से कोयले का उत्पादन आरंभ होने पर राज्य को प्रतिदिन करीब 2.7 रैक कोयले की मिल सकेगी। एक अनुमान के अनुसार इस ब्लॉक में 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष कोयले का उत्पादन होने की संभावना है। इस नए ब्लॉक से कोयले की सालाना एक हज़ार रैक मिलेगी।
- उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार को परसा ईस्ट व कांता बेसिन में फेज वन में कोयला लगभग समाप्त हो जाने के कारण कोयले का संकट गहराने लगा था। परसा ईस्ट कांता बेसिन के दूसरे चरण के 1136 हेक्टेयर वन भूमि में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की क्लियरेंस भी पिछले दिनों मिल गई है।

संगीत नाटक अकादमी अवार्ड

चर्चा में क्यों ?

9 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू द्वारा राजस्थान के गाज़ी खान बरना को लोक संगीत के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिये संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया।

प्रमुख बिंदु

- गाज़ी खान बरना राजस्थान के जैसलमेर ज़िले से संबंधित हैं।
- इन्होंने राजस्थानी लोक संगीत की मांगणियार परंपरा की समृद्ध विरासत को आत्मसात् किया है।
- वर्तमान में इनकी प्रसिद्धि एक मँजे हुए खड़ताल वादक की है।
- लोककला के क्षेत्र में इनके योगदान को देखते हुए वर्ष 2002 में इन्हें राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद के कार्यकाल में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

11 अप्रैल, 2022 को राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद (CMRETAC) का कार्यकाल दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि इस परिषद का गठन 7 मार्च, 2020 को किया गया था और इसका कार्यकाल मार्च 2022 तक निर्धारित था।
- आयोजना (ग्रुप-एक) विभाग की ओर से जारी इस आदेशानुसार मुख्यमंत्री इस सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं तथा डॉ. अरविंद मायाराम उपाध्यक्ष एवं शासन सचिव आयोजना परिषद के सदस्य सचिव हैं।
- इसी तरह डॉ. गोविंद शर्मा मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त एवं प्रमुख शासन सचिव मुख्यमंत्री भी परिषद में सदस्य के रूप में शामिल है।
- परिषद के विस्तारित कार्यकाल के लिये अन्य सदस्यों में डॉ. राथिन रॉय, डॉ. अशोक गुलाटी, अनिल अग्रवाल, लक्ष्मी निवास मित्तल, नैना लाल किदवई, डॉ. देवी शेट्टी, विक्रम मेहता, नावेद खान, डॉ. शिव कुमार सरीन, सुश्री फैथ सिंह, नंदिता दास, डॉ. ज्योतिंद्र जैन, कविता सिंह, अमित कपूर, विजय कुमार, राजीव गौडा, मंगू सिंह, प्रदीप एस. मेहता, डॉ. दिनेश सिंह, अरुण मायरा, डॉ. नरेश त्रेहन, महेश व्यास, डॉ. प्रणव सेन तथा यामिनी अबयर शामिल हैं।

तीन राष्ट्रीय राजमार्गों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा सड़क दुर्घटनामुक्त

चर्चा में क्यों ?

13 अप्रैल, 2022 को राजस्थान के गृह, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने बताया कि बजट घोषणा की अनुपालना में प्रदेश के तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत सड़क दुर्घटनामुक्त बनाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- अतिरिक्त मुख्य सचिव ने शासन सचिवालय में 'सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम' के संबंध में हुई बैठक में यह जानकारी दी।
- जिन तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत सड़क दुर्घटनामुक्त बनाया जाएगा, उनमें शाहजहाँपुर से अजमेर (एनएच-448), बर-बिलाड़ा-जोधपुर (एनएच-25) व सीकर से बीकानेर (एनएच-110) राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को एंबुलेंस के रेस्पॉन्स टाइम को और बेहतर बनाने तथा सड़क दुर्घनाओं में गंभीर घायलों को तुरंत अस्पताल पहुँचाने वाले गुड सेमेरिटन को 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना' के तहत पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया।
- उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस (आईरैड) एप्लीकेशन के ज़रिये सड़क दुर्घटना से संबंधित डेटा को तुरंत अपलोड किया जाना चाहिये, ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिये उनका वैज्ञानिक विश्लेषण हो सके।

सांस्कृतिक कार्यक्रम 'फोक सफर' का आयोजन

चर्चा में क्यों ?

13 अप्रैल, 2022 को राजस्थान पर्यटन विभाग और यूनेस्को के सहयोग से जयपुर के जवाहर कला केंद्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम 'फोक सफर' का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- 'फोक सफर' में डेनमार्क के कलाकारों का संगीत, उनके देश तथा पड़ोसी क्षेत्रों की लोक परंपराओं की विरासत के शानदार प्रदर्शन के साथ मांगणियार कलाकारों द्वारा प्रदेश के मरु अंचल के पारंपरिक संगीत एवं ताल का रंगारंग प्रदर्शन किया गया, जिसमें लंगा संगीत एवं कालबेलिया नृत्य का आयोजन भी शामिल था।
- कार्यक्रम में डेनिश कलाकारों का नेतृत्व मारेन हॉलबर्ग और जोर्गन डिकमेस ने किया और मांगणियार कलाकारों का नेतृत्व शिव, बाड़मेर से आए मंज़ूर खान मांगणियार ने किया।
- फोक सफर में जोधपुर के सालावास की दरियाँ, बाड़मेर के पटोदी की जूतियाँ, चोहटन की एप्लिक और जैसलमेर के पोकरण के बर्तनों सहित अन्य हस्तशिल्प वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया।

एपीआई का 77वाँ राष्ट्रीय सम्मेलन 'एपिकॉन, 2022'

चर्चा में क्यों ?

14 अप्रैल, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, सीतापुरा में एसोसिएशन ऑफ फिजीशियंस ऑफ इंडिया (एपीआई) के 77वें राष्ट्रीय सम्मेलन 'एपिकॉन, 2022' का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर चिकित्सकों को वर्ष 2020 एवं 2021 के प्रतिष्ठित जीवराज मेहता अवार्ड से सम्मानित किया और चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा लिखित विभिन्न पुस्तकों का विमोचन भी किया।
- एपीआई जयपुर चैप्टर की ओर से आयोजित इस 4 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन 17 अप्रैल, 2022 तक किया जाएगा।
- गौरतलब है कि एपीआई का यह वार्षिक सम्मेलन 10 साल बाद जयपुर में आयोजित किया जा रहा है।
- इस सम्मेलन में 6,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय चिकित्सक भाग लेंगे। सम्मेलन में चिकित्सा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिये आउटस्टैंडिंग डेलेब्रेशंस एंड डिबेट्स होंगे, ताकि 'पिंक ऑफ हेल्थ' में रहने के लिये इनोवेटिव तरीकों की खोज की जा सके।
- 'एपिकॉन, 2022' चिकित्सा के अभ्यास के साथ-साथ हाय-टेक सम्मेलनों के आयोजन में टेक्नोलॉजी को फर्स्ट हैंड अनुभव करने के लिये एक मील का पत्थर साबित होगा। सम्मेलन औद्योगिक भागीदारों को भी पर्याप्त प्रदर्शन और व्यावसायिक अवसर प्रदान करेगा।
- ऐतिहासिक रूप से 'एपिकॉन' भारत के चिकित्सकों और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सबसे बड़े चिकित्सा सम्मेलनों में से एक है।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम व टीएचडीसी के बीच अक्षय ऊर्जा पार्क के लिये करार

चर्चा में क्यों ?

15 अप्रैल, 2022 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन (टीएचडीसी) के बीच राजस्थान में 10 हज़ार मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने हेतु ऋषिकेश में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस समझौता ज्ञापन पर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से तकनीकी निदेशक सुमित माथुर और टीएचडीसीआईएल की ओर से महाप्रबंधक हाइब्रिड एनर्जी बिजनेस संजय खेर ने हस्ताक्षर किये।

- इस एमओयू के अनुसार राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का क्रियान्वयन व विकास दोनों कंपनियों द्वारा गठित संयुक्त उपक्रम स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) के माध्यम से किया जाएगा।
- इस नवीकरणीय ऊर्जा पार्क परियोजनाओं के निर्माण के दौरान लगभग 10,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर भी सृजित होने की संभावना है।
- उल्लेखनीय है कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में टीएचडीसीआईएल द्वारा इस ऐतिहासिक कदम से ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पर शिखर सम्मेलन में भारत सरकार द्वारा 2030 तक अपनी 50 प्रतिशत ऊर्जा ज़रूरतें रीन्यूएबल एनर्जी से पूरा करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी योगदान मिलेगा।
- इसके साथ ही राजस्थान राज्य में इन नवीकरणीय अक्षय सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास से सस्ती एवं पर्यावरण के अनुकूल सौर बिजली से राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी गति मिलेगी।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान 10 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है।
- केंद्र सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान अब केवल सोलर ही नहीं, अपितु नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सभी प्रदेशों को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर आ गया है। राजस्थान में करीब 8 लाख करोड़ रुपए के एमओयू एलओआई पर सहमति हुई है।
- हाल ही समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में 3000 मेगावाट क्षमता से अधिक क्षमता विकसित की जा चुकी हैं, जबकि पिछले तीन सालों में प्रदेश में 6552 मेगावाट क्षमता विकसित हुई है।

राजस्थान में स्थापित हुआ एल-रूट सर्वर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राज्य सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने की पहल के रूप में भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर में एल-रूट सर्वर स्थापित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस सर्वर को राज्य सरकार द्वारा इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स (आईसीएएनएन) के साथ मिलकर स्थापित किया गया है।
- आईसीएएनएन के इस रूट सर्वर से अब राजस्थान डोमेन नेम सिस्टम के लिये किसी रूट सर्वर पर निर्भर नहीं है।
- इस व्यवस्था के बाद अब यदि पूरे एशिया या भारत में किसी तकनीकी गड़बड़ी या प्राकृतिक विपदा के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी में दिक्कत आती है, तो भी यह राजस्थान में बिना किसी रुकावट के चलती रहेगी। साथ ही इससे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित होगी।
- गौरतलब है कि राजस्थान एल-रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

अब तक 143 हेरिटेज संपत्तियों को प्रमाण-पत्र जारी

चर्चा में क्यों ?

18 अप्रैल, 2022 को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर राजस्थान पर्यटन विभाग की निदेशक डॉ. रश्मि शर्मा ने बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा अभी तक 143 हेरिटेज संपत्तियों को प्रमाण-पत्र जारी किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- ये हेरिटेज संपत्तियाँ देशी-विदेशी पर्यटकों के साथ-साथ डेस्टीनेशन वेडिंग और फिल्म शूटिंग लोकेशन के रूप में बहुत लोकप्रिय हैं, साथ ही विभागीय वेबसाइट के माध्यम से इन संपत्तियों का प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा।

- इन हेरिटेज होटलों के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार के परिलाभ, जैसे- संपरिवर्तन शुल्क, आबकारी बार लाइसेंस शुल्क, स्टांप ड्यूटी और शहरी विकास कर में छूट इत्यादि उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
- प्रदेश में स्थापत्य विरासत के रूप में किले, महल, हवेलियाँ इत्यादि बहुतायत में उपलब्ध हैं, इन पुरासंपत्तियों में से ज़्यादातर संपत्तियाँ निजी स्वामित्व में हैं, जिनका संरक्षण वर्तमान समय की महती आवश्यकता है।
- राज्य सरकार द्वारा निजी स्वामित्व की हेरिटेज संपत्तियों के संरक्षण और इन संपत्तियों के हेरिटेज होटल एवं अन्य पर्यटन इकाइयों के रूप में उपयोग को बढ़ावा देने के लिये हेरिटेज प्रमाण-पत्र प्रदान करने की योजना लागू की गई, जिसे जुलाई 2021 में निवेशकों के अनुरूप सरलीकृत किया गया है।
- देश भर में संचालित हेरिटेज होटलों में से दो-तिहाई से अधिक हेरिटेज होटल राजस्थान राज्य में हैं। पर्यटन विभाग द्वारा राजकीय संपत्तियों को भी हेरिटेज प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे अर्थात् विश्व धरोहर दिवस को संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिये मनाया जाता है, साथ ही यह दिवस देश-प्रदेश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने, उनके सवर्द्धन और संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिये मनाया जाता है, ताकि लोग अपनी संस्कृति और परंपरा को करीब से समझ सकें।

स्मार्ट सिटी रैंकिंग में उदयपुर दूसरे स्थान पर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में उदयपुर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- देश की 100 स्मार्ट सिटी की इस रैंकिंग में उदयपुर 122.8 अंकों के साथ पहली बार टॉप-2 में पहुँचा है, जबकि सूरत शहर 128.80 अंक के साथ पहले स्थान तथा 120.39 अंक के साथ आगरा तीसरे नंबर पर हैं।
- उदयपुर के अतिरिक्त राजस्थान के अन्य शहरों में जयपुर 7वें, कोटा 16वें और अजमेर 18वें नंबर पर हैं।
- गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी उदयपुर में अब तक 233.77 करोड़ की लागत से सीवेज नेटवर्क, पानी की लाइन डालने, सड़क किनारे डक्टिंग, अंडरग्राउंड वायरिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सॉलिड वेस्ट प्लांट एवं बायो माइनिंग तथा कचरे के प्लांट जैसी 77 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं, जबकि 653.12 करोड़ की 21 परियोजनाएँ कार्यरत हैं।

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, 2022

चर्चा में क्यों ?

20 अप्रैल, 2022 को राजस्थान के रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, 2022 का आयोजन 30 अप्रैल से 9 मई, 2022 तक जवाहर कला केंद्र के दक्षिणी परिसर में किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि सहकारिता क्षेत्र में राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है, जो कई वर्षों से सहकार मसाला मेले का आयोजन करता आ रहा है।
- उपभोक्ता संघ के प्रबंध निदेशक वी.के. वर्मा ने बताया कि सहकार मेले में सहकारी संस्थाओं को आकर्षक पैकिंग, मसालों की शुद्धता, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य और सहकारिता की विश्वसनीयता बनाये रखने के निर्देश दिये गए हैं। सहकार मसाला मेले में साबुत और पिसे हुए मसालों के साथ ही मौके पर ही मसाला पीसकर उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी होगी।
- सहकार मसाला मेले के आयोजन से उत्पादक किसान और आम नागरिक दोनों को ही लाभान्वित किया जा सकेगा। सहकार मसाला मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य जयपुरवासियों को शुद्ध मसाले उपलब्ध कराना है।

इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी और 23 राज्य विश्वविद्यालयों के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित

चर्चा में क्यों ?

20 अप्रैल, 2022 को राजस्थान राजभवन में राज्य के 23 सरकारी विश्वविद्यालयों और रेडक्रॉस सोसायटी, राजस्थान के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए, साथ ही रेडक्रॉस सोसायटी, राजस्थान की नई वेबसाइट redcross.rajasthan.gov.in का लोकार्पण भी किया गया।

प्रमुख बिंदु

- एमओयू के अनुसार रेडक्रॉस और विश्वविद्यालय आपदाओं और जोखिम में रोकथाम-राहत कार्य, जल स्वच्छता एवं सफाई प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रबंधन, पारिस्थितिकी आधारित कार्यों, स्वास्थ्य सेवाओं और रक्तदान के बारे में जागरूकता लाने के लिये आपसी सहयोग से कार्य करेंगे।
- इन एमओयू के बाद विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में भी रेडक्रॉस की प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियों का विस्तार हो सकेगा। अब राज्य विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत लाखों विद्यार्थियों को रेडक्रॉस की गतिविधियों से जुड़ने का अवसर मिल सकेगा।
- रेडक्रॉस सोसायटी राजस्थान की नई वेबसाइट में नई सदस्यता और स्वयंसेवक के रूप में जुड़ने के लिये आवेदन एवं आर्थिक सहयोग देने की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है।
- इस अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल और रेडक्रॉस सोसायटी, राजस्थान शाखा के पदेन अध्यक्ष कलराज मिश्र ने कहा कि राजस्थान में रेडक्रॉस की गतिविधियों को गति देने के लिये सभी ज़िलों में ज़िला कलक्टरों के समन्वय से इकाइयों का गठन किया जा चुका है।
- उन्होंने रेडक्रॉस राज्य इकाई की कार्यकारिणी का गठन भी शीघ्र करने के निर्देश दिये, ताकि प्रदेश में आपदाओं और संकट के समय रेडक्रॉस का सबल, सक्रिय और सशक्त रूप दिखाई दे। उन्होंने प्रदेश में समयबद्ध अभियान चलाकर रेडक्रॉस सोसायटी को प्रभावी करने के निर्देश दिये।

मार्च 2022 में राज्य का सभी वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक 380.58 रहा

चर्चा में क्यों ?

19 अप्रैल, 2022 को राजस्थान के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव डॉ. ओमप्रकाश बैरवा ने बताया कि मार्च 2022 में सभी वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक 380.58 (प्रावधानिक) रहा।

प्रमुख बिंदु

- राज्य के मासिक सामान्य थोक मूल्य पर आधारित मुद्रा स्फीति की वार्षिक वृद्धि दर (मार्च 2021 की तुलना में मार्च 2022 में) 9.10 प्रतिशत रही है। इसी तरह प्राथमिक वस्तु समूह सूचकांक 407.52 एवं ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उप-स्नेहक समूह सूचकांक 571.06 तथा विनिर्मित उत्पाद समूह सूचकांक 300.16 रहा।
- मार्च 2022 में प्राथमिक वस्तु समूह का सूचकांक गत माह की तुलना में 1.35 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 407.52 रहा है। प्राथमिक वस्तु समूह के सूचकांक में वृद्धि का मुख्य कारण इसके अंतर्गत कृषि उप समूह सूचकांक में 1.48 प्रतिशत एवं खनिज उपसमूह सूचकांक में 0.30 प्रतिशत की वृद्धि का दर्ज होना रहा है।
- कृषि मद समूह के खाद्य पदार्थ उपसमूह सूचकांक में 3.10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि अखाद्य पदार्थ उपसमूह सूचकांक में 0.78 प्रतिशत का कमी रही।
- आलोच्य माह में प्राथमिक वस्तु समूह के खाद्य/अखाद्य पदार्थ उप समूह के अंतर्गत अनाजों में (4.19 प्रतिशत), दालों में (3.17 प्रतिशत), फलों में (25.92 प्रतिशत), दूध (1.28 प्रतिशत), मसालों (8.18 प्रतिशत), रेशा (0.54 प्रतिशत) एवं अन्य अखाद्य पदार्थों (0.96 प्रतिशत) की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई, वहीं सब्ज़ियों में (16.84 प्रतिशत), अंडा, मांस व मछली (0.14 प्रतिशत) एवं तिलहन (1.36 प्रतिशत) की कीमतों में कमी दर्ज की गई।
- खनिज उपसमूह के अंतर्गत आलोच्य माह में 0.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई, जिसमें मुख्यत: चाँदी (5.30 प्रतिशत), स्टेटाइट (सोपस्टोन) (0.09 प्रतिशत) एवं इमारती पत्थर (0.58 प्रतिशत) की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई, जबकि जिप्सम (0.35 प्रतिशत), चूना पत्थर (0.63 प्रतिशत) तथा ईंटों (0.14 प्रतिशत) की कीमतों में कमी आई हैं।

- प्राथमिक वस्तु समूह सूचकांक में वार्षिक आधार पर मुद्रा स्फीति की दर में मार्च 2021 की तुलना से 16.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
- ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उप-स्नेहक समूह का सूचकांक मार्च 2022 में गत माह के सूचकांक 567.98 की तुलना में 0.54 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 571.06 पर रहा। सूचकांक में वृद्धि का प्रमुख कारण कोयला सबग्रुप में 4.21 प्रतिशत तथा पेट्रोल, डीज़ल एवं एलपीजी में 0.65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होना रहा है।
- वार्षिक आधार पर मार्च 2021 की तुलना में ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उप-स्नेहक समूह में 2.34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
- विनिर्मित उत्पाद समूह का सूचकाँक मार्च 2022 में गत माह फरवरी 2022 के सूचकांक 297.71 की तुलना में 0.82 प्रतिशत बढ़कर 300.16 पर पहुँच गया है। सूचकांक में वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य उत्पादों (2.07 प्रतिशत), मादक पेय पदार्थ एवं तंबाकू उत्पाद (0.07 प्रतिशत), कताई-बुनाई व परिष्करण (0.59 प्रतिशत), अधातु एवं खनिज उत्पाद (0.04 प्रतिशत), बुनियादी कीमती व लौह धातु (1.75 प्रतिशत) तथा सामान्य प्रयोजन मशीनरी (0.02 प्रतिशत) की कीमतों में वृद्धि होना रहा है, जबकि लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद (1.63 प्रतिशत) एवं केमिकल (0.23 प्रतिशत) की कीमतों में कमी रही है।
- वार्षिक आधार पर मार्च 2021 की तुलना में विनिर्मित उत्पाद समूह में 7.46 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये चूरू ज़िला कलक्टर सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

21 अप्रैल, 2022 को सिविल सेवा दिवस पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूरू ज़िला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- 'खेलो इंडिया' अभियान के तहत ज़िले में हुए उत्कृष्ट कार्यों और बेहतर उपलब्धियों के लिये चूरू ज़िले को मिले इस पुरस्कार के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने ज़िला कलक्टर को 20 लाख रुपए का चेक एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।
- यह पुरस्कार ज़िले में विकसित खेल केंद्रों, खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त पदक, महिला खिलाड़ियों, पैरा-खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व, फिट इंडिया-खेलो इंडिया में ज़िला प्रशासन द्वारा किये गए नवाचार में युवा खिलाड़ियों की व्यापक स्तर पर भागीदारी के लिये दिया गया है।
- उल्लेखनीय है कि ज़िले में भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के द्वारा स्वीकृत खेलो इंडिया के 8 केंद्र एथलेटिक्स राजगढ़, द्रोणाचार्य राष्ट्रीय मुक्केबाज़ी अकादमी राजगढ़, टेबल टेनिस ज़िला स्टेडियम चूरू, हॉकी गाजुवास, हैंडबॉल एकेडमी लोहा, भारोत्तोलन, कुश्ती, मुक्केबाज़ी उर्मिला खेल अकादमी न्यांगल बड़ी संचालित हैं, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक हैं।
- ज़िला स्टेडियम चूरू में साई के 6.30 करोड़ से नवनिर्मित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन (IAAF) द्वारा प्रमाणित वर्ड क्लास सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाया गया है।
- गौरतलब है कि ज़िले के 34 खिलाड़ियों द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 2019 और 2020 में प्रतिनिधित्व किया गया था। इनमें से 10 खिलाड़ियों द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 2020 में पदक प्राप्त किये गए, जो राजस्थान को मिले पदकों का 20 प्रतिशत था।
- ज़िले में सन् 2019 से 2021 तक महिला एवं पैरा-खिलाड़ियों का खेल में अच्छा प्रतिनिधित्व रहा तथा महिला और पैरा-खिलाड़ियों ने पदक प्राप्त किये। ज़िला प्रशासन द्वारा नवाचार के रूप में ज़िले के विद्यालयों में पोषण और स्वास्थ्य जागरुकता अभियान चलाकर बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक कर फिट इंडिया प्रोग्राम को सफल बनाया गया।

जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट के लिये 672.5 करोड़ रुपए की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

21 अप्रैल, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय, जोधपुर की समीक्षा बैठक में जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिये 672.5 करोड़ रुपए की संशोधित राशि को मंज़ूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- यह संस्थान जोधपुर में 66 बीघा भूमि में स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में 400 करोड़ रुपए फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिये आवंटित किये गए थे।
- इस संस्थान को स्टेट ऑफ द आर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। संस्थान का परिसर शून्य अपशिष्ट, शून्य बिजली और शून्य पानी के साथ नेट ज़ीरो कैंपस होगा। यह भवन पर्यावरण हितैषी भवन होगा। राजस्थान राज्य में अपनी तरह का यह पहला निर्माण होगा।
- प्रारंभ में संस्थान के लिये 1,400 छात्रों की क्षमता की सोच रखी गई थी। अब यूजी, पीजी और पीएचडी कार्यक्रमों की संख्या को देखते हुए छात्रों की संख्या को 4,000 तक संशोधित किया गया है।
- राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट के तहत चार स्कूल प्रस्तावित हैं। इसमें स्कूल ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट्स एंड मार्केट्स, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टंस एंड एनालिटिक्स और स्कूल ऑफ फिनटेक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैं।
- संस्थान में स्मार्ट क्लासरूम, ट्यूटोरियल रूम, लेक्चर थिएटर, फ्लिप क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर सेंटर, सेंट्रल लाइब्रेरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेमिनार हॉल बोर्ड रूम 1,000 छात्रों के लिये ऑडिटोरियम, खेल सुविधाएँ आदि होंगी।
- संस्थान में गेस्ट हाउस, एकेडमिक ब्लॉक, कार्यशालाएँ, छात्रावास, फैकल्टी ब्लॉक, गैर-शिक्षण ब्लॉक, डीन और निदेशक निवास सहित 11,55,500 वर्ग फीट में निर्माण होगा। इसमें शिक्षण, अनुसंधान और विकास के लिये अत्याधुनिक आईटी सुविधाएँ होंगी।

तीन दिवसीय 69वीं राज्यस्तरीय सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

21 अप्रैल, 2022 को राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में 69वीं राज्यस्तरीय तीन दिवसीय सीनियर पुरुष एवं महिला वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता का विधिवत् शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस प्रतियोगिता का आयोजन 24 अप्रैल तक किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि ज़िला कबड्डी संघ द्वारा पहली बार जैसलमेर में राज्यस्तरीय सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।
- इस प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में 31 ज़िलों की टीमें एवं महिला वर्ग में 24 ज़िलों की टीमें भाग ले रही हैं।
- इस अवसर पर अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने कहा कि पहली बार प्रदेश में पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो खेल जगत के लिये अनुकरणीय कदम है।

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2022 के लोगो का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

25 अप्रैल, 2022 को राजस्थान की प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता श्रेया गुहा ने सहकार भवन में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2022 के लोगो का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि जवाहर कला केंद्र में 30 अप्रैल से 9 मई, 2022 तक राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2022 का आयोजन किया जाएगा।
- इस अवसर पर सचिव श्रेया गुहा ने कहा कि योजनाबद्ध ढंग से कार्य करते हुए जैविक उत्पादों को कॉनफैड बड़े स्तर पर लोगों को उपलब्ध कराए तथा गुणवत्ता को बरकरार रखे।
- उन्होंने कहा कि दो वर्षों में 4171 ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाना है। इसके लिये समयबद्ध रूप से लक्ष्य आवंटन के अनुरूप कार्य किया जाए, ताकि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन सुनिश्चित किया जा सके।

नवजीवन योजना

चर्चा में क्यों ?

26 अप्रैल, 2022 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने विभागीय अधिकारियों को नवजीवन योजना के अंतर्गत शामिल जातियों के सर्वे का कार्य तीन माह में पूरा कर अवैध शराब के व्यवसाय में लिप्त व्यक्तियों और उनके परिवारों को चिह्नित करने के निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु

- नवजीवन योजना का उद्देश्य अवैध शराब के निर्माण, भंडारण एवं व्यवसाय में लिप्त व्यक्तियों तथा ऐसे परिवारों को योजना से लाभान्वित कर उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाना है। इसके लिये ऐसे व्यक्तियों एवं परिवारों को चिह्नित किया जाना आवश्यक है।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि इस योजना में पूर्व में 14 जातियाँ शामिल थीं, लेकिन बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में 16 और जातियों को इसमें शामिल किया गया है। पूर्व में इस योजना के अंतर्गत सभी ज़िलों में सर्वे करवा कर लगभग 97,827 व्यक्तियों को चिह्नित किया गया है।
- योजना के तहत 30 जातियों- कंजर, सांसी, भाट, भाण्ड, नट, राणा, डोम, ढोली, मोगिया (मोग्या), बावरिया, बेडिया, बागरिया, सिरकीवाला, चौबदार, गाडोलिया, बंजारा, कालबेलिया, भोपा, नायक, गाडिया लुहार, पारदी, भेड़कुट, रैबारी, सिकलीगर, सीगडीवाल, रंगास्वामी, नाथ, बाजीगर, गुजराती एवं जंगलिया को शामिल किया गया है।
- योजना के तहत अवैध शराब के व्यवसाय में लिप्त सभी 30 जातियों के व्यक्तियों और ऐसे परिवारों का डोर-टू-डोर सर्वे करवाया जाएगा तथा उनका डिजिटल डेटाबेस तैयार करवाया जायेगा।

आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण

चर्चा में क्यों ?

27 अप्रैल, 2022 को सरहदी ज़िले जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया गया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि आकाश मिसाइल भारत में बनी ज़मीन-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे ज़मीन पर किसी भी वाहन या स्थायी जगह से दागा जा सकता है।
- आकाश मिसाइल परिवार में अब तक कुल 2 मिसाइलें थीं, अब आकाश प्राइम इस वर्ग की तीसरी अहम मिसाइल बन गई है। ये मिसाइलें हवा में किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट को नष्ट करने में सक्षम है।
- इस मिसाइल की रेंज आसमान में 30 किलोमीटर तक है और ये एक बार में 60 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकती है। ये मिसाइल हवा में भी नियंत्रित की जा सकती है और खुद भी सेंसर्स के ज़रिये ड्रोंस से लेकर फाइटर जेट्स तक को निशाना बना सकती है।

- आकाश प्राइम ऊँचाइयों पर उड़ रहे फाइटर जेट्स से लेकर ड्रोंस, क्रूज मिसाइल, एयर-टू-सर्फेस मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को भी आसानी से भेदने में सक्षम है। ये बेसिक आकाश मिसाइल के मुकाबले करीब 10 गुना ज़्यादा इलाके को स्कैन कर सकती है।
- मिसाइल की खास बात है कि यह दुश्मन के विमानों का पता लगाकर आसमान में ही ध्वस्त करने में सक्षम है। यह मिसाइल विमान को 30 किमी. दूर और 18 हज़ार मीटर ऊँचाई तक टारगेट कर सकती है।
- आकाश मिसाइलों को डीआरडीओ ने विकसित किया है और इनका उत्पादन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की ओर से किया जाता है। इसके सर्विलाँस, रडार, कमांड सेंटर और लॉन्चर को बनाने की ज़िम्मेदारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (बीईएल), टाटा पावर स्ट्रैटिजिक इंजीनियरिंग डिविजन और लार्सन एंड टूब्रो के पास है।

ब्लॉक हेल्थ मेले का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

28 अप्रैल, 2022 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने राज्य के अलवर ज़िले के उमरैण में ब्लॉक हेल्थ मेले का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- यह मेला चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से आयोजित किया गया।
- इस मेले का मुख्य उद्देश्य आमजन को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखना तथा बीमारियों के उपचार के साथ ही विभागों की योजनाओं का लाभ दिलाना है।
- टीकाराम जूली ने बताया कि राज्य सरकार निरोगी राजस्थान के संकल्प के साथ राज्य के प्रत्येक नागरिक को बेहतर एवं नि:शुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिये संकल्पबद्ध है।
- गौरतलब है कि राज्य में 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' को 1 मई, 2021 से शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत अब 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज किया जा सकेगा।

आईबीसी एक्सीलेंस अवार्ड, 2021

चर्चा में क्यों ?

28 अप्रैल, 2022 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री कौशल किशोर ने राजस्थान आवासन मंडल (RHB) को वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित आईबीसी अवार्ड से सम्मानित किया है।

प्रमुख बिंदु

- यह अवार्ड नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इंडियन बिल्डिंग कॉन्ग्रेस के 25वें वार्षिक सम्मेलन में प्रदान किया गया।
- राजस्थान आवासन मंडल के मुख्य अभियंता के.सी. मीणा को भी उनकी विशिष्ट सेवाओं, प्रतिबद्धता तथा समर्पण के लिये आईबीसी प्रेसीडेंशियल अवार्ड से सम्मानित किया गया।
- इंडियन बिल्डिंग कॉन्ग्रेस ने बोर्ड को यह अवार्ड एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट-2021 श्रेणी में मंडल के उच्च आय वर्ग के आवासीय प्रोजेक्ट 'कंस्ट्रक्शन ऑफ एचआईजी 104 फ्लैट्स' (बी+एस+13) के लिये प्रदान किया है।
- इंडियन बिल्डिंग कॉन्ग्रेस (IBC) पेशेवरों का एक राष्ट्रीय निकाय है, जो लागत प्रतिस्पर्द्धा वाली प्रौद्योगिकियों के साथ टिकाऊ निर्मित पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिये स्थापित किया गया था।
- शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के समर्थन से स्थापित यह निकाय हर साल विभिन्न श्रेणियों के भवनों में 'निर्मित पर्यावरण में उत्कृष्टता' (एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट) के लिये आईबीसी अवार्ड प्रदान करता है।

स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली 'गगन' का इस्तेमाल

चर्चा में क्यों ?

28 फरवरी, 2022 को इंडिगो ने एक बयान जारी कर बताया कि इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली 'गगन' का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई है।

प्रमुख बिंदु

- यह लैंडिंग राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर हुई।
- 'गगन' का उपयोग रनवे के पास विमान की लैंडिंग के लिये मार्गदर्शन करने हेतु किया जाता है।
- इसकी सटीकता उन छोटे हवाई अड्डों पर, जहाँ उपकरण लैंडिंग प्रणाली (आईएलएस) स्थापित नहीं की गई है, विशेष रूप से उपयोगी है।
- इसके साथ ही भारत, अमेरिका और जापान के बाद अपनी एसबीएएस (Satellite Based Aaugmentation System) प्रणाली रखने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है।
- उल्लेखनीय है कि 'गगन' भारत का उपग्रह आधारित हवाई नौवहन तंत्र है, जिसे इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है।

दृष्टि The Vision